



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 आषाढ़ 1934 (श०)

(सं० पटना 327) पटना, वृहस्पतिवार, 12 जुलाई 2012

गृह विभाग

आदेश

23 जून 2009

बिहार मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्य (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2009

सं० ओ०/रा०मा०आ०-६०/२००८-४३०६—मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1994 का संख्या 10) की धारा-४१ की उप-धारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।**— (१) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बिहार मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्य (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2009 होगा,
(२) ये आयोग के गठन की तिथि से प्रवृत्त समझें जायेंगे।
2. **परिभाषा।**— इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—
(क) “अध्यक्ष” से अभिप्रेत है बिहार मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष,
(ख) “सदस्य” से अभिप्रेत है बिहार मानवाधिकार आयोग का सदस्य,
(ग) “आयोग” से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-२१ की उप-धारा (१) के अधीन गठित राज्य मानवाधिकार आयोग,
(घ) “अधिनियम” से अभिप्रेत है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1994 का संख्या 10),
(ड.) उन अन्य सभी शब्दों और पदों, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में दिए गए हैं।
3. **वेतन तथा भत्ते।**— (क) अध्यक्ष को उतना वेतन तथा भत्ता भुगतान किया जायेगा जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन तथा भत्ते के बराबर होगा।
(ख) सभी सदस्यों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन/भत्ते देय होंगे।
परन्तु यह भी कि यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य अपनी नियुक्ति के समय, राज्य सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के अन्तर्गत पेंशन (अशक्तता या क्षति पेंशन से भिन्न) प्राप्त कर रहे हों या उसने ऐसा करने का पात्र होने पर लेने का चयन किया था तो, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में सेवा के अन्तर्गत उनका वेतन:—
(१) उस पेंशन की राशि तक,

- (2) यदि उन्होंने, पद ग्रहण करने से पहले, ऐसी पूर्व सेवा के अन्तर्गत उन्हें देय पेंशन के एक भाग के बदले में उसका संराशित (Commututed) मूल्य प्राप्त किया था तो पेंशन की उस भाग की राशि तक; और
- (3) उनके द्वारा लिए या उपयोग किए जा रहे या लिए या उपयोग किए जाने वाले किसी अन्य प्रकार की सेवा नियुक्ति के लाभ तक घटा दिया जाएगा।
4. छुट्टी।— अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर अध्यक्ष या सदस्य को निम्नलिखित रूप से छुट्टी अनुमान्य होगी:—
- (1) सेवा के प्रत्येक संपूरित कैलन्डर वर्ष या उसके भाग के लिए पन्द्रह दिन की दर से उपार्जित छुट्टी;
 - (2) सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए बीस दिन की दर से चिकित्सकीय प्रमाण—पत्र के आधार पर या निजी कार्य के लिए अर्द्ध—वेतन छुट्टी और अर्द्ध—वेतन छुट्टी के लिए छुट्टी वेतन उपार्जित छुट्टी के दौरान अनुदेय छुट्टी वेतन के आधे के समतुल्य होगा;
 - (3) अध्यक्ष या किसी सदस्य के विवेकानुसार अर्द्ध—वेतन छुट्टी पूर्ण वेतन छुट्टी में परिवर्तित की जा सकती है यदि वह अस्वस्थता के आधार पर की जाती है तथा किसी सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी के चिकित्सीय प्रमाण—पत्र द्वारा समर्पित हो;
 - (4) एक पदावधि में वेतन भर्तों के बिना अधिकतम 180 दिन तक की असाधारण छुट्टी।
5. छुट्टी यात्रा रियायत।—(1) अध्यक्ष उन्हीं दरों से और उसी मापदण्ड पर और उन्हीं शर्तों पर, जो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए लागू है, छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार होंगे;
- (2) सदस्यों को उन्हीं दरों से और उसी मापदण्ड पर उन्हीं शर्तों पर, जो पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू है, छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार होंगे।
6. छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी।— अध्यक्ष या किसी सदस्य की छुट्टी स्वीकृत करने, या अस्वीकृत करने या स्वीकृत की गई छुट्टी को रद्द करने की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी।
7. यात्रा एवं चिकित्सा भत्ते।— अध्यक्ष और सदस्य, यात्रा के दौरान (जिसके अन्तर्गत आयोग में कार्यभार ग्रहण करने या आयोग से उसकी पदावधि की समाप्ति पर गृह नगर जाने के लिए की गई यात्रा भी है) एवं चिकित्सा भत्ता के लिए:—
- नियम 5 के उप-नियम (1) से (2) एवं इसके परन्तुक के अनुरूप अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश के अनुरूप अनुमान्य होगा।
8. भविष्य निधि।— बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के कार्यकाल की अवधि किसी भी परिस्थिति में भविष्य निधि या भविष्य निधि लाभ के लिए विचारणीय नहीं होगी।
9. अवशिष्ट उपबंध।— अध्यक्ष और सदस्यों की उन सेवा शर्तों का जिनके लिए इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, क्रमशः उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यथास्थिति और उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश को तत्समय लागू नियमों तथा आदेशों द्वारा अवधारण किया जाएगा।
10. नियम शिथिल करने की शक्ति।— राज्य सरकार को इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल करने अथवा इसके क्रियान्वयन में उत्पन्न कठिनाईयों के निराकरण करने की शक्ति प्राप्त होगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
रविशंकर कुमार सिन्हा,
अवर सचिव।

23 जून 2009

सं० ओ०/रा०मा०आ०-६०/२००८-४३०६, दिनांक 23.06.09 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-३४८ के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा उसका प्राधिकार पाठ समझा जाएगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
रविशंकर कुमार सिन्हा,
अवर सचिव।

The 23rd June 2009

THE BIHAR HUMAN RIGHTS COMMISSION CHAIRPERSON AND MEMBER (SALARIES, ALLOWANCES AND OTHER TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE) RULES, 2009

No. ओ०/रा०मा०आ०-६०/२००८-४३०६—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 41 of the protection of Human Rights Act, 1993 (Act No.10 of 1994).
The State Government makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement—

(1) These rules may be called the Bihar Human Rights Commission, Chairperson and Members (Salaries, Allowances and other terms and conditions of service) Rules. 2009.

(2) They shall come into force from the date of constitution of commission.

2. Definitions. — In these rules, unless the context otherwise requires:-

- (a) “Chairperson” means the Chairperson of the Bihar Human Rights Commission.
- (b) “Member” means a member of the Bihar Human Rights Commission.
- (c) “Commission” means the Bihar Human Rights Commission constituted under sub-section (1) of section 21 of the Act.
- (d) “Act” means the Protection of Human Rights Act. 1993 (Act No. 10 of 1994).
- (e) The words and expressions used in these rules but not defined in these rules and defined in the Act shall have meaning assigned to them in Act.

3. Salary and Allowances. —

- (a) The Chairperson shall be paid salary and allowances which are equal to the salary and allowances of Chief Justice of High court.
- (b) The Member shall be paid salary and allowances which are equal to the salary and allowances of a Judge of High Court.

Provided further that if the Chairperson or a Member at the time of his appointment was in receipt of, or being eligible so to do, elected to draw, a pension (other than disability or wound pension) in respect of any previous service under the Government of the Union or Government of the State, his salary in respect of service as a Chairperson or a Member, as the case may be, shall be reduced.

- (1) By the amount of that pension;
- (2) if he had, before assuming office, received in lieu of a portion of pension due to him in respect of such previous service, the commuted value thereof, by the amount of that portion of pension: and
- (3) by any other form of retirement benefits, being drawn or availed of or to be drawn or availed of by him.

4. Leave. —A person, on appointment as Chairperson or as a Member, as the case may be shall be entitled to leave as follows:-

- (1) Earned leave at the rate of fifteen days for every completed calendar year of service or a part thereof;
- (2) Half pay leave on medical certificate or on private affairs, at the rate of twenty days in respect of each completed year of service and the leave salary or half pay leave shall be equivalent to half to the leave salary admissible during the earned leave;
- (3) Leave on half pay can be commuted to full pay leave at the discretion of Chairperson or a Member if it is taken on medical ground and is supported by a medical certificate from the competent authority;
- (4) Extra ordinary leave without pay and allowances up to maximum of one hundred eighty days in on term of office.

5. Leave Travel Concession. —

-
- (1) The Chairperson shall be entitled to leave travel concession at the same rates and at the same scales and on the same conditions as are applicable to the Chief Justice of Patna High Court.
- (2) The Member shall be entitled to leave travel concession at the same rates and at the same scales and on the same conditions as are applicable to a Judge of Patna High Court.
- 6. Authority Competent to Grant Leave.**—The power to grant or refuse leave to the Chairperson or a Member and to revoke leave granted to him shall vest in the Governor.
- 7. Travel and Medical Allowances.**—The Chairperson and the Members, while on tour (including the journey undertaken to join the Commission or on expiry of his term with the Commission to proceed to his home town) and for medical allowances:-
The Chairperson and Members shall be entitled to travel allowances as applicable by them as Chairperson and Members as per provisions of sub-rule (1) to (2) of Section 5 and proviso thereof.
- 8. Provident Fund.**—The period served as Chairperson or Members of the Commission shall not be taken into consideration in any circumstance for calculation of provident fund or provident fund benefits.
- 9. Residuary Provisions.**—The conditions of the service of the Chairperson and the Members for which no express provisions made in these rules shall be determined by the rules and orders for the time being applicable to the Chief Justice of the High Court or a Judge of High Court as the case may be and to the sitting Judge of the High Court respectively.
- 10. Power to Relax Rules.**—The State Government shall have the power to relax the provision of any of these rules or to remove of difficulties arising in its implementation.

By order of the Governor of Bihar,
RAVI SHANKAR KUMAR SINHA,
Under Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 327-571+1000-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>